अल्मोड़ा जिले में भिकियासैण तहसील को बसोट के साथ जोड़ने के लिए सड़क मार्ग

2823. **श्री राजनाथ सिंहः** क्या **ग्रामीण और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में भिकियासैण तहसील मुख्यालय को विकास केन्द्र बसोट के साथ जोड़ने के लिए मोटर सड़क मार्ग के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस योजना के अधीन मंजूरी दी गई तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो, तो सरकार उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे देगी; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सन् 2000 तक सभी को पेय जल

2824. **श्री गोविन्दाराम मिरीः क्या ग्रामीण और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 ईस्वी तक सभी ग्रामीण लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोई ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे विशेष कार्य योजना बनाएं और कार्यान्वित करें ताकि 2000 ईस्वी तक ग्रामीण लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

Eradication of Poverty in Rural Areas

2825. SHRI LACHMAN SINGH: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the assessment of government regarding eradication of poverty in rural areas of the country during 1993-94 and 1996-97, State-wise;

(b) the basis of arriving at such conclusions; and

(c) the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) to (c) The problem of rural poverty has been on the top of the development agenda of the Government and accordingly Government has been taking several steps for eradication of poverty.

The Planning Commission estimates the incidence of poverty in rural and urban areas of different States in the country utilising the quinquennial National Sample Survey (NSS) data on consumer expenditure. The latest estimates of poverty is available for the year 1993-94 based on the NSS consumer expenditure data of 50th Round. The State-wise assessment of poverty in the rural areas for 1993-94 following the recently adopted official methodology which is based on the Report of the Expert Group is given in the Statement. (*See* below).

The existing poverty eradication programmes for self employment and wage employment would continue in the Ninth Five year Plan. These programmes would be redesigned to make them more effective as instruments of poverty eradication.